attached. (*See* below). Remaining information to the extent available would be collected and laid on the Table of the Rajya Sabha.

Statement

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the Company	Year ending	Written down value of investment in machinery
1	M/s. Lyka Labs. Pvt. Ltd.	June, 1983	5·19
2	M/s. Warner Hindustan Limited	November, 1983	113 59
3	M/s. German Remedies Ltd.	December, 1983	266·40
4	M/s. Cadila Labs. Pvt. Ltd.	December, 1983	134·07
5	M/s. Roussel Pharmaceuticals India Limited	December, 1983	62·54
6	M/s. Duphar Interfran	December, 1983	106·01

सोनीपत की ई॰सी॰ई॰ कंपनी में दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजा

2058. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री ई॰ सी॰ ई॰ कंपनी, सोनीपत में हुई दुर्घटना के संबंध में 30 जुलाई, 1984 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 119 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मृतक व्यक्ति का नाम और पता क्या है और उसकी मृत्यु का कारण क्या था ; कंपनी ने उसके परिवार वालों के लिए क्या व्यवस्था की है; और उसके परिवार को अब तक कितना रुपया दिया जा चुका है ; और

(ख) क्या जो व्यक्ति आंशिक रूप से अपंग हो गए हैं, उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Expansion of legal aid programmes

2059. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to consider further schemes for expansion of legal aid programme and also exempt the poor from payment of stamp duty and court fees and make the programme effective during the Seventh Five Year Plan period; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL): (a) and (b) Further schemes for expansion of legal aid programmes are under consideration of the Government. No decision has been taken for exempting the poor from payment of stamp duty and court fees. The matter is under the consideration of the Government in consultation with the State Governments.